



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 2 जुलाई, 2002/11 आषाढ़, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

भारत के संविधान के अर्त्तनियम 348 के खण्ड (3) के अर्त्तर्गत आपेक्षित सरकार की अधिसूचना सं० रैव-डी (जी) 6-8/2001, दिनांक 4 जून, 2002 का हिन्दी अनुवाद।

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 4 जून, 2002

संख्या रैव-डी (जी) 6-8/2001.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ग्राम शामिलत भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का 18) की धारा 13 और हिमाचल प्रदेश अधिकतम भू-जोत सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का 19) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं० रैव-डी (जी) 6-33/86-11, तारीख 20 अक्तूबर, 1993 द्वारा अधिसूचित और 5 नवम्बर, 1993 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और सर्वसाधारण की सूचना के लिए इन्हें एवद्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

इन नियमों से सम्भाव्य प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति इन नियमों के सम्बन्ध में यदि कोई आशेष करना चाहे या सुझाव देना चाहे तो वह इन्हें सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002 को

इन प्रारूप नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर भेज सकेगा ;

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव यदि कोई हों, पर इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ; अर्थात्:—

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन), नियम, 2002 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 4 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 4 में :—

(क) खण्ड (iii) में “व” शब्द के पश्चात् आए “50 प्रतिशत से अधिक अपंगता वाले” शब्दों के स्थान पर “अपंग” शब्द रखा जाएगा ।

(ख) खण्ड (vi) में “,” चिन्ह के पश्चात् “और” शब्द का लोप किया जाएगा ।

(ग) खण्ड (vii) में “.” चिन्ह के स्थान पर “;” चिन्ह प्रति स्थापित किया जाएगा; और

(घ) विद्यमान खण्ड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

(viii) किसी वाणिज्यिक इकाई अथवा जैव प्रौद्योगिकी से संबन्धित तकनीकी इकाई की स्थापना हेतु, किसी भी प्रयोजन के लिए बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा स्वरोजगार हेतु हरित गृह अथवा टीसूकल्चर की स्थापना हेतु ;

(ix) भूमिहीन वास्तविक हिमाचली द्वारा आवासीय गृह निर्माण के लिए या प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों के पुर्नवास के लिए ;

(x) व्यक्तियों द्वारा ग्राम और खादी बोर्ड उद्योगों के अधीन प्रायोजित किसी इकाई की स्थापना हेतु ;

(xi) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसी अन्य कल्याण योजना के लिए ;

(xii) किसी सामुदायिक प्रयोजन के लिए खेल क्रिया कलाओं/युवा क्लबों/महिला मण्डलों/अन्य व्यष्टि/रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं की स्थापना ; और

(xiii) व्यक्तियों द्वारा वैज्ञानिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु ।”

3. नियम 5 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 5 में :—

(क) खण्ड (8) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“परन्तु यह और कि राज्य सरकार आपवादिक मामलों में लोक प्रयोजन के लिए बीस बीघा से अधिक क्षेत्र का पट्टा प्रदान कर सकती है ।”

(ख) विद्यमान खण्ड (8) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

“(9) किसी वाणिज्यिक इकाई अथवा जैव प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित तकनीकी इकाई की स्थापना हेतु, किसी भी प्रयोजन के लिए बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा स्वरोजगार हेतु हरित गृह अथवा टीसू कल्चर इकाई की स्थापना हेतु ।

सरकार द्वारा यथा अनुमोदित परियोजना/स्कीम के अनुसार ।

(10) आवास गृह के लिए

4 बिस्वा

(11) खेल गतिविधियों के लिए

वास्तविक अपेक्षित क्षेत्र या 2 बीघा, जो भी कम हों ।

(12) महिला मण्डल/युवा क्लब

4 बिस्वा ।”

4. नियम 6 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 6 के खण्ड (7) में “व” शब्द के पश्चात् आए “50 प्रतिशत से अधिक अपंगता वाले व्यक्तियों” शब्दों के स्थान पर “अपंग व्यक्ति” शब्द रखे जाएंगे ।

5. नियम 7 का प्रतिस्थापन.—उक्त नियमों के विद्यमान नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रति-
स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

“7. पट्टे की मंजूरी,—इन नियमों के अधीन पट्टे की मंजूरी राज्य सरकार द्वारा, उस अवधि के लिए जैसी वह ठीक समझे, दी जाएगी:

परन्तु राज्य सरकार किसी भी मामले में 99 वर्ष की अवधि से अधिक भूमि का पट्टा प्रदान नहीं करेगी ।”

6. नियम 8 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (1) में,—

(क) “(X)” “व” शब्द के पश्चात् आए “50 प्रतिशत से अधिक अपंगता वाले व्यक्तियों” के स्थान पर “अपंग व्यक्ति” शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) खण्ड (X) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात्,—

(xi) भूमिहीन वास्तविक हिमाचली द्वारा आवासीय प्रयोजनों के लिए प्राकृतिक आपात पीड़ितों के पुर्नवास/महिला मण्डलों/युवा क्लबों के लिए ।

पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की अन्तिम अधिकतम बाजारी कीमत का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष की औसत बाजारी कीमत से दुगुनी, जो भी कम हो ।

(xii) व्यक्तियों द्वारा वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए ।

पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की अन्तिम अधिकतम बाजारी कीमत का 8 प्रतिशत या पांच वर्ष की औसत बाजारी कीमत से दुगुनी जो भी कम हो ।

(xiii) सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाईटी द्वारा, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी कल्याण योजना के लिए इसी प्रकार

पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की अन्तिम अधिकतम बाजारी कीमत का 8 प्रतिशत या 5 वर्ष की औसत बाजारी कीमत की दुगुनी जो भी कम हो ।”

से रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा
खेल गतिविधि की स्थापना एवं
सामुदायिक उद्देश्य के लिए रजिस्ट्री-
कृत संस्थान।

7. नियम 13 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 13 में,—

- (i) उप-नियम (1) में “जहां वह मंजूरी प्राधिकारी नहीं है” चिन्ह व शब्दों का लोप किया जाएगा।
- (ii) उप-नियम (2) में “उप-मण्डल अधिकारी (सिविल) के माध्यम से “शब्दों व कोष्ठकों के पश्चात “मण्डलायुक्त” शब्दों के स्थान पर “आयुक्त राजस्व” शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (iii) विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित नियम (3) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—
“(3) आयुक्त (राजस्व) सभी मामलों को प्रशासनिक विभागों के माध्यम से पट्टे पर भूमि प्रदान करने के लिए, उपयुक्तता और न्यायोचितता के सम्बन्ध में उनकी सिफारिशों/रिपोर्ट/टिप्पणियों सहित मंजूरी प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।”

8. नियम 20 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 20 में “उसके द्वारा मंजूर पट्टों को रद्द कर सकेगा और अन्य मामलों में “शब्द के स्थान पर” पट्टे को रद्द करेगा और” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

9. नियम 26 का प्रतिस्थापन.—विद्यमान नियम 26 के स्थान पर, निम्नलिखित नया नियम 26 प्रतिस्थापित किया जाएगा, —

“26. पुनर्विलोकन. —(1) हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम, 2002 के प्रवर्तन से पूर्व, क्लर्क, मण्डलायुक्त, वित्तायुक्त और राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश का राज्य सरकार के पुनर्विलोकन के अधीन होंगे जो इस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसे वह उचित समझे :

परन्तु यह कि ऐसे आदेश तब तक उपांतरित और बदले नहीं जाएंगे जब तक कि उसके द्वारा प्रभावित पक्षों को व्यक्तिगत या उसके/उनके विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से, उसके/उनके दावे के समर्थन में, सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया हो।

(2) पुनर्विलोकन के लिए आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे आदेश के पारित होने के नब्बे दिन के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, या आवेदक जब तक मंजूरी प्राधिकारी का समाधान नहीं करता कि उसके पास आवेदन अवधि के भीतर प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण थे।

10. नियम 27 का प्रतिस्थापन.—विद्यमान नियम 27 के स्थान पर निम्नलिखित नया नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“27. पुनर्निरीक्षण राज्य सरकार, यथास्थिति, क्लर्क, मण्डलायुक्त या वित्तायुक्त द्वारा निपटाए गए किसी मामले के अभिलेख को किसी भी समय मंगवा सकेगी, और ऐसे आदेश, जैसे वह उचित समझे, पारित कर सकेगी :

परन्तु यह कि ऐसे आदेश तब तक उपांतरित और बदले नहीं जाएंगे जब तक कि उसके द्वारा प्रभावित पक्षों को व्यक्तिगत या उसके/उनके विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से उसके/उनके दावे के समर्थन में, उपस्थित होने और सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।

11. प्ररूप-ग का सशोधन.—उक्त निममों के साथ संलग्न प्ररूप-ग में पैरा-10 के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा :

“परन्तु यह कि पट्टा अवधारित करने से पूर्व पट्टाधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा और वित्तीय संस्थान को भी इसके विषय में सूचित किया जाएगा।”

आदेश द्वारा,

रवि डिंगरा,
वित्तायुक्त एवं सचिव (राजस्व)।

[*Authoritative English Text of this Government Notification No. Rev. D(G)6-8/2001, dated June, 2002 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th June, 2002

No. Rev. D (G) 6-8/2001.—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Himachal Pradesh village Common lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act 18 of 1974) and section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh lease Rules, 1973 notified *vide* this dipartment notification No. Rev. D (G) 6-33/86-11, dated the 20th October, 1973 and published in Rajpatra Himachal Pradesh (Extra Ordinary) dated the 5th November, 1993 and the same is hereby published in Rajpatra, Himachal Pradesh for general information of the public.

If any person likely to be affected by these rules has any objection (s) or suggestion (s) to make in respect of these rules, he may send the same to the Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh Shimla-171002 within 30 days from the date of publication of these draft rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period specified above, shall be considered by the State Government before finalising these rules, namely :—

DRAFT RULES

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Lease (Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 4.—In rule 4 of the Himachal Pradesh lease Rules, 1993 (herein after referred to as the said rules) :—

(a) in clause (iii), after the words “persons”, words, figure and sign “having disability by more than 50%” shall be deleted.

(b) in clause (vi), the word “and” after the singh “;” shall be deleted;

(c) in clause (vii), for the singh “.” the singh “;” shall be substituted; and

(d) After the existing clause (vii) the following clauses shall be added, namely :—

- “(viii) for the establishment of Commercial unit or technical Unit relating to bio-technology, setting up of a green house or tissue culture unit, for self employment by unemployed individuals for any purpose;
- (ix) for the construction of residential house by the land less bonafide Himachali or for the rehabilitation of sufferers of natural calamities;
- (x) to establish any unit sponsored under the village and Khadi Board Industries by the individuals;
- (xi) Any other welfare scheme sponsored by the Government of India/State Government;
- (xii) establishment of sports activities/youth clubs/Mahila Mandals/any other person/registered institutions for any community purpose; and
- (xiii) to promote the scientific activities by the individuals”.

3. *Amendment of rule 5.*—In rule 5 of the said rules.—

(a) After proviso to clause (B), the following proviso shall be inserted, namely :—

(a) After proviso to clause (B), the following second proviso shall be inserted, namely :—

“Provided further that the State Government may grant the lease of an area exceeding 20 bighas for public purpose in exceptional cases.”

(b) After the existing clause (8), the following clauses shall be added, namely :—

“(9) establishment of a commercial unit or technical unit relating to bio-technology like setting up of a green house, tissue culture unit for self employment by un-employed individuals for any purpose.	According to the project/scheme as approved by the Government.
--	--

(10) For residential house	4 biswas
----------------------------	----------

(11) for sports activities	Actual area required or two bighas whichever is less.
----------------------------	---

(12) Mahila Mandals/youth clubs.	4 biswas”
----------------------------------	-----------

4. *Amendment of rule 6.*—In clause (7) of rule 6 of the said Rules :—

After the word “persons” the words, figure and sign “having disability by more than 50%” shall be deleted.

5. *Substitution of rule 7.*—For the existing rule 7 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

“7. *Sanction of lease.*—The lease under these rules shall be sanctioned by the State Government for a period as it may deem fit :

Provided that the State Government shall not grant the lease of land in any case for a period exceeding 99 years.”

6. *Amendment of rule 8.*—In sub-rule (1) of rule 8 of the said rules :—

(a) “X” After the word “persons” the words, figure and sign “having disability by more than 50%” shall be deleted.

(b) After clause (x), the following new clauses shall be added, namely :—

“(xi) Residential purposes by the landless bonafide Himachali/rehabilitation of sufferers of natural calamities/ Mahila Mandals/Youth clubs. 5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less;

(xii) Scientific activities by the individuals. 8% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less;

(xiii) Any welfare scheme sponsored by the Government of India/State Government, if executed by a society registered under the societies Registration Act, 1860 establishment of a sports activity by a society similarly registered and a registered institution for community purpose. 8% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years; whichever is less;

7. *Amendment of rule 13.*—In rule 13 of the said rules,—

1. In sub rule (1), the sign and words, “Where he is not the sanctioning authority” shall be deleted.

(ii) in sub-rule (5), after the words and brackets “through Sub-Divisional officer (Civil), for the words “Divisional Commissioner”, the words and bracket “Commissioner (Revenue)” shall be substituted.

(iii) For the existing sub-rule (3), the following rule (3) shall be substituted, namely,—

(3) “The Commissioner (Revenue) shall refer all the cases to the sanctioning authority through the Administrative Departments in relation to the justification and appropriateness for the grant of land on lease with their recommendations/report/comments”.

8. *Amendment of rule 20* —In rule 20 of the said rules, for the words, “cancel the lease sanctioned by him and in other cases” the words, “cancel the lease” shall be substituted.

9. *Substitution of rule 26.*—For the existing rule 26, the following new rule 26 shall be substituted, namely,—

“26. *Review.*—(1) The orders passed by the Collector, Divisional Commissioner, Financial Commissioner and the State Government prior to the enforcement of the Himachal Pradesh lease (Amendment) Rules, 2002 shall be subject to review by the State Government which may pass such orders on it as it may deem fit:

Provided that such an order shall not be modified or revised unless reasonable opportunity has been given to the party(ies) effected thereby, of being heard either in person or through his/their legal representative in support of his/their claim.

(2) An Application for review shall not be entertained unless it is made within ninety days from the passing of the order, or unless the applicant satisfies the sanctioning authority that he had sufficient cause for not making the application within that period.”

10. *Substitution of rule 27.*—For the existing rule 27, the following new rule 27 shall be substituted, namely,—

“27. *Revision.*—The State Government may at any time call for the records of any case disposed of by the Collector or the Divisional Commissioner or Financial Commissioner, as the case may be, and pass such orders as it may deem fit :

Provided that such an order shall not be modified or reversed unless reasonable opportunity has been given to the party(s) affected thereby, to appear and be heard either in person or through his/their legal representative in support of his/their claim(s).

11. *Amendment of Form-C.*—In Form-C appended to the said rules in para-10 at the end, the following proviso shall be added, namely,—

“Provided further that before determining the lease, an opportunity of being heard shall be given to the lessee and the Financial Institution shall also be informed above the same.”

By order,

RAVI DHINGRA,
F. C.-cum-Secretary (Revenue).